

joining you in congratulating our scientists on the success of 'Prithvi.' They are also expressing their concern for 'Agni.' You may make a statement on 'Agni' at your convenience....(Interruptions).... Now we are in the midst of Zero Hour.

**RE. GRAVE LAW AND ORDER
SITUATION IN U.P.—CONTD.**

उपसभापति: राजनाथ सिंह जी, आप अपना वक्तव्य क्लैड करें। You go back to what is happening in Uttar Pradesh.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: (उत्तर प्रदेश) मैडम, प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश के भी हैं। वह इलेक्शन में वहां 40 दफा जा सकते हैं तो अभी उत्तर प्रदेश में जो आग लगी है अपहरण और हत्याओं की(व्यवधान)....

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): He is going to Orissa.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Yes, he is going to Orissa.

But, can he not stay for another five minutes here?

We all share the agony of Orissa.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is going there with other leaders also. That is why Shri Sikander Bakht was kind enough to cooperate in making the statement by the hon. Prime Minister.

श्री राजनाथ सिंह: (उत्तर प्रदेश)-मैडम, मुझे वह कहने में संकोच नहीं है कि श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ऐसे कद्दावर नेता थे कि जिन के कारण उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से 4 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी को जनाधार मिला था। वहां फैले आतंक और हिंसा के खिलाफ चर्टान की तरह खड़ा होनेवाले अगर कोई नेता थे, तो वह श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे। मैडम, मैंने जिन बिंदुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है, उस में

2 जून का राज्य अतिथि गृह हत्याकांड भी है जिस के वे चरमदीय गवाह थे। उस मामले में सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इस का भी वह संज्ञान ले। साथ ही जिन परिस्थितियों में उन के फायर आर्म्स के लायसेंस निरस्त किए गए और उन की हत्या के 9 दिन बाद सारे फायर आर्म्स वापिस हो गए, इस का भी सीबीआई संज्ञान ले। मैडम, मैं आश्वस्त हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी के द्वारा केवल पिस्तौल चलाने वाले हाथों की ही जानकारी नहीं मिलेगी बल्कि पिस्तौल चलाने के लिए उकसाने वाले जो दिमाग हैं, उन की भी जानकारी हो जाएगी और सारे ऐसे लोग पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे।

मैडम, मैं एक और बड़ी घटना का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यू०पी० कालेज में पुलिस के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गयी जिस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दो छात्र श्री सवेन्द्र मिश्र और मनोरंजन सिंह व यू०पी० कालेज के एक भूतपूर्व छात्र श्री उपेन्द्र सिंह की हत्या हो गयी। मैडम, इस समय उत्तर प्रदेश का पूरा छात्र समुदाय आंदोलित है और मुझे लगता है कि कहीं ऐसे हालात न पैदा हो जाएं कि उत्तर प्रदेश का पूरे-का-पूरा छात्र समुदाय आंदोलित हो उठे और वहां की सारी व्यवस्था को उष्ण करने की स्थिति में पहुंच जाए।

मैडम, मैं मांग करता हूँ कि उन छात्रों की हत्या के लिए गोली चलाने में भी जिम्मेदार लोग हैं, उन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और जिन की गोली से हत्या हुई है, ऐसे अधिकारी अथवा ऐसे पुलिस-कर्मियों के विरुद्ध धारा-302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही जो छात्र मारे गए हैं, उन के परिवारों को कम-से-कम पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए।

यह मैं मांग करता हूँ। साथ ही बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के सारे मामले की न्यायिक जांच करवाई जाने की भी मैं मांग करता हूँ।

मैडम, आज उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था भी बुरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गई है। अधिकारियों का लगातार स्थानान्तरण चल रहा है। एक एक आई०पी० एस०, आई०ए०एस० अधिकारी ऐसे हैं, जिनका वर्ष में आठ-आठ बार स्थानान्तरण हुआ है। कानपुर के एस०एस०पी० का स्थानान्तरण एक वर्ष में आठ-आठ बार हुआ है। ऐसे ऐसे अधिकारियों को पदस्थापित किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध मुजफ्फरनगर कांड में गंभीर

चांज रहे हैं, जिनके विरुद्ध चार्जशीट अदालत में सबमिट हो चुकी है।

उपसभापति: आप खतम करें। यहां मेरे पास दूसरे नाम भी हैं। सिन्गे रज़ी साहब का भी नाम है।
....(व्यवधान)....

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं केवल एक उदाहरण भ्रष्टाचार के संबंध में देना चाहूंगा। मैं आरोप लगाने में संकोच नहीं करना चाहता कि** * करोड़ों रुपए का आयुर्वेद का घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ। सारा हिन्दुस्तान इस बात को जानता है। सी०बी०आई० ने पत्र लिखकर राजभवन से अनुरोध किया कि हमें अदालत में चार्जशीट सबमिट करने की इजाजत राजभवन से मिलनी चाहिए, लेकिन सी०बी०आई० के उस अनुरोध के बावजूद आज तक सी०बी०आई० को राजभवन से यह इजाजत नहीं मिली कि करोड़ों रुपए के आयुर्वेद घोटाले के अभियुक्त के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की जा सके। एक अजीबो-गरीब स्थिति आज उत्तर प्रदेश की पैदा हो गई है। मैं राजनैतिक द्वेष के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा, मैडम।

उपसभापति: एक बात मैं आपको बता दूं कि हम यहां उत्तर प्रदेश के ऊपर कोई डिस्क्शन नहीं कर रहे हैं, स्पेशल मेशन कर रहे हैं। सिक्का प्रधानमंत्री के एक मिनट की स्टेटमेंट के, 16 मिनट में से 15 मिनट आप बोल चुके हैं। दूसरे नाम भी मेरे पास हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, हमने भी नाम दिए हुए हैं।(व्यवधान)....

उपसभापति: आपका नाम नहीं है। मेरे पास।
....(व्यवधान)....

श्री सतीश अग्रवाल: राजस्थान मैडम, उत्तर प्रदेश की स्थिति गंभीर है, इसलिए या तो इसी पर चर्चा होगी अन्यथा कोई और दूसरी चर्चा नहीं होगी।(व्यवधान)....

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, एक मिनट और मैं कहना चाहूंगा।(व्यवधान).... मैडम, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि आज से चार महीने पहले वहां चुनाव हो चुका है, लेकिन आज तक वहां पर कोई लोकप्रिय सरकार का गठन नहीं हो सका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन जजों की बैच ने जो फैसला दिया है, वह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जहां प्रेसीडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन नोटिफिकेशन को उसने क्वैस कर दिया, वहीं पर इन तीन जजों के बैच ने यह भी कहा है, जिसका मैं यहां उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं। इसमें, मैडम,

यह कहा है कि—

"In their judgment, the Bench called the Proclamation ratified by the Parliament 'issued in colourable exercise of power and based wholly on irrelevant and extraneous grounds'."

और, यह भी कहा है कि—

"The Government did not initiate discussions with leaders of major political parties."

इसमें यह भी कहा गया है कि—

"A floor test should have been thought of or considered."

तीसरी बात, यह भी कही है हाईकोर्ट के बैच ने, कि—

"There was no serious attempt by the Governor to preserve democracy."

यानी डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कोई पहल नहीं की। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए, यहां पर सरकार बनाने की संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए। लेकिन, आज तक उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैडम, मैं राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता,

लेकिन क्योंकि आज वह केवल कंस्टीट्यूशनल हैड नहीं है बल्कि वह एक एग्जीक्यूटिव हैड के रूप में काम कर रहे हैं इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि क्यों उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारा पूरा विश्वास है कि जब तक राज्यपाल उत्तर प्रदेश में आज के, राज्यपाल बने रहेंगे, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को कभी भी बहाल नहीं किया जा सकता, कानून और व्यवस्था की स्थिति में कभी भी सुधार नहीं लाया जा सकता। मैं मांग करना चाहता हूं, मैडम, कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को तुरन्त बरखास्त किया जाना चाहिए क्योंकि तभी जाकर उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति वापस हो सकती है।
....(व्यवधान)....

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम,

उपसभापति: एक सेकेण्ड।(व्यवधान).... एक सेकेण्ड।(व्यवधान).... प्लीज, एक मिनट।(व्यवधान).... आप बैठिए। आप बैठिए।(व्यवधान)....

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्री जी के बारे में जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल निराधार और असत्य है।(व्यवधान)....

उपसभापति: आप बैठिए।(व्यवधान)....

श्री ईश दत्त यादव: और समाचार पत्रों में जो छपा है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलह से ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इन्वोल्व हैं।(व्यवधान).... मैडम, यह समाचार पत्रों में जो आ रहा है, उससे लगता है,(व्यवधान).... भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलह से यह हत्या हुई है।(व्यवधान).... इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इन्वोल्व हैं और रक्षा मंत्री के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह बिल्कुल निराधार ही, नहीं, असत्य है।(व्यवधान).... इस हत्या के लिए मुझे भी चिंता है और साग देश चिंतित है(व्यवधान).... भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह से यह हत्या हुई है। जब आप शिक्षा मंत्री थे तो कितने बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई थीं, इसका भी आप लेखा-जोखा दीजिए(व्यवधान).... महोदया, राजनाथ सिंह ने बिल्कुल असंगत और निराधार आरोप लगाए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ और जो लोग उसमें मरे हैं, मैं अपनी पार्टी की ओर से उनके प्रति शोक प्रकट करता हूँ और मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हैं, उनको सजा दी जाए और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए(व्यवधान)....

उपसभापति: आप जरा शांति करेंगे हाऊस में, बैठिए(व्यवधान).... ईश दत्त जी, बैठ जाइए(व्यवधान)....

श्री ईश दत्त यादव: आपने एक सिटिंग एम्प्ली के ऊपर और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि नहीं लगाया है? श्री राजनाथ सिंह इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस हत्या में कौन से लोग शामिल हैं(व्यवधान).... राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित होकर रक्षा मंत्री के खिलाफ आप बोले(व्यवधान)....

SHRI SATISH AGARWAL: While Rome was burning, Nero was fiddling!

राजभवन में हैलीपैड बनना चाहिए, यह उनकी माँ योरीटी है।

श्री राजनाथ सिंह: राजभवन के लिए हैलीपैड बना है वहां पर।*

THE DEPUTY CHAIRMAN: One second(Interruptions).... Please sit down. Mr. Chairman has permitted you and I allowed you to speak for a long time. If you do not want the Governor and if you feel he is not doing his job properly, there is a proper way to move a motion about it, if you like.

SHRI SATISH AGARWAL: This is a preface to that motion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Being a very senior person, you know that.

SHRI SATISH AGARWAL: I have only said that this is a preface to the motion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But the preface should come in writing in a proper order. My duty as the Presiding Officer is and has always been to see that whatever you want to do, you do it in a proper way. There is a way to do it. So please come in a proper manner. But it is not proper to speak about a constitutional authority who is appointed by the President, whom you do not like, perhaps—and I have no objection to that much, but....(Interruptions)....

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Rajasthan): The question of our not liking is that he is not behaving properly.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am just putting it in my own way. If some Members in this House feel that way, that he is not performing his duty according to what is expected, then there is a way to move it. If you like. I can read the matter. If you don't want it, then please confine yourself to law and order. If somebody is not performing his duty, there are way to mention it. It should be done in a proper manner but not irresponsibly on the floor of the House because it is not proper.

SHRI SIKANDER BAKHT: We are only demanding that he should be dismissed because, for whatever is happening in

Uttar Pradesh, it is the Governor who is responsible.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Because what I am reading...

विपक्ष के नेता श्री सिकन्दर बाख्त: मैडम, इस वक्त कोई रेगुलर मोशन आपके सामने नहीं है ... (व्यवधान)...

اگر کسی سیکندر باخت: میڈم- اس وقت کوئی ریگولر موشن آپ کے سامنے نہیں ہے ... (صراحت)...

उपसभापति: अगर रेगुलर मोशन नहीं है तो फिर ... (व्यवधान)...

SHRI SIKANDER BAKHT: We can demand.

SHRI SATISH AGARWAL: There is a difference between a Governor acting as a Governor in a State where there is an elected Government and a Governor acting in a State in an executive capacity on behalf of the President. Here in U.P. the situation is different. He is exercising executive functions. He is not only the constitutional head of the State but he is also the executive head of the State.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Agarwal Ji, I have not written the Constitution. Nor have I written the law. I am not the author of the Constitution. I am only telling you what is written here. It is entirely up to you how you want to implement it. But the Constitution is not written by me.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: When there is a motion under rules there is no question of Constitution.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is, if you like. There is a provision that you move a substantive motion. I am only trying to tell you what could be proper.

SHRI SIKANDER BAKHT: We will abide by what you say.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. सैयद सिन्धे रज़ी, आप बोलिए।

सैयद सिन्धे रज़ी (उत्तर प्रदेश): अभी कुछ देर पहले जो नज़ारा आपने देखा कि एक करता है क्रिया और दूसरा करता है उस पर प्रतिक्रिया और उसके बाद शोर-शराबा होता है। बिल्कुल 8-9 साल से हमारा उत्तर प्रदेश इन्हीं गतिविधियों का शिकार हो रहा है। एक तरफ साम्प्रदायिक तत्व कुछ बात करता है और दूसरी तरफ उसके जवाब में कुछ सो-काल्ड र्यूडो सेक्युलरिस्ट जो है वह आगे बढ़ते हैं। ... (व्यवधान)

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: हमें भी सो-काल्ड कम्युनिस्ट कह दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ... (व्यवधान)

सैयद सिन्धे रज़ी: हमारे प्रदेश की करोड़ों-करोड़ जनता आज प्रसित है, प्रभावित है ऐसी चीजों से। विकास रुका हुआ है, विकास की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। पिछले 3-4 महीने के अंदर विशेष तौर से प्रशासन लुज-पुंज हो गया है। एक विस्फोटक स्थिति पर आज पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, इस बात से तो दो राय नहीं हो सकती। जो हत्याएं हो रही हैं उसमें साधारण नागरिक की बात क्या की जाए। कत्तान मारे जा रहे हैं, पुलिस कत्तान मारे जा रहे हैं, एसडीओएस मारे जा रहे हैं, पूर्व प्रधान मंत्री का घर सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता के गनर्स मारे जा रहे हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं और मैं कहता हूँ कि नज़दत दिवेदी की भी हत्या हत्याओं की एक कड़ी है। लेकिन यदि हमने इन इश्यूज को राजनीतिक इश्यू बनाकर तथा जनता के हित के जो हैं उनके ऊपर बात न करके इसी स्थिति के ऊपर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह भी कोई मुनासिब बात नहीं है। सीबीआई-इंक्वायरी की हमने डिमांड की है। सीबीआई-इंक्वायरी की बात मानी जा चुकी है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह कहता हूँ कि इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच-पड़ताल होनी चाहिए और यह राजनीतिक हत्याएं जो हैं बंद होनी चाहिए। अभी हमारे साथी ने यहां पर कहा, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह देखना होगा कि आज उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति उभरकर आ रही है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी, प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, एक इन्स्टीट्यूशन को आपने यहां पर जो भी कहा उसके गुण

और अवगुण में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जनता सारी परेशानियों से गुजर रही है उसकी जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चा सरकार की है और मुझे खेद होता है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार वहां के जिम्मेदार मंत्रीगण जो हैं, वह राज भवन को अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस बात को पूरी शर्मानाक समझता हूं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह का राष्ट्रपति शासन हो चुका है लेकिन इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूं कि हमारे जो मौजूदा राज्यपाल जी हैं, वह पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। जब उन पर प्रत्यक्ष रूप से एक्सेशन कास्ट किए जा रहे हैं, वह निस्संदेह तौर पर एक बहस का मुद्दा बन चुके हैं तो इस सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में वह अपनी जिम्मेदारी निभाएँ। राज्यपाल का शासन इंटैल्फ कुछ शासन नहीं होता जब तक राष्ट्रपति या केन्द्र सरकार उसके संबंध में अपना प्रयास नहीं करते। अब जिम्मेदारी आती है केन्द्र सरकार की। या तो वहां से राज्यपाल को हटाएं, स्थानांतरित करें या वहां पर कोई ऐसी कमेटी बनाएं जो संसद सदस्यों की कमेटी हो, आल पार्टी कमेटी हो। वह वहां पर जाकर एक नजर रख सके कि वहां की परिस्थिति जो है वह इतनी अधिक खराब क्यों हो रही है।

आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का फैसला किया है, मैं उसके गुण और अवगुण में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि कहीं आपके इस प्रयास से जिस तरह कानून अपने हाथ में ले लेने का अपने अपने कैडर को आह्वान किया है वहां पर सिविल वार की सिचुएशन न हो जाए। ... (व्यवधान) आपने कहा है कि राज्यपाल को राज भवन से निकलने नहीं देंगे और अगर राज्यपाल राजभवन से निकलकर किसी पब्लिक फंक्शन में जाएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। निश्चित रूप से वहां पर एक टकराव की परिस्थिति पैदा होगी। ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयानात से किसी समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। मुख्य रूप से हम सबको सिर जोड़ कर बैठना चाहिए। यदि वहां राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई काम गलत हो रहा है, निहित स्वार्थों को वहां पोषित किया जा रहा है और निश्चित रूप से यह जो अखबारों में छप रहा है, उससे पता चलता है कि वहां पर सत्तापोषित गुंडागर्दी हो रही है। अब यदि ऐसी सत्तापोषित गुंडागर्दी होगी तो निश्चित रूप से हम संसद सदस्यों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं।

अभी बनारस में जैसे हुआ, बनारस में निहत्थे विद्यार्थियों के ऊपर खुलेआम गोली चलाई गई। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई ग्रुप, कोई समुदाय, कोई भी गुट यदि वहां के शासन के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, उसकी राजनीतिक हत्या करवा दी जाती है, यह बहुत ही गलत बात है। विद्यार्थियों पर गोली चलाना एक बहुत ही अशोभनीय दुर्घटना है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और मैं तो कहूंगा कि इसकी जांच किसी हाई कोर्ट के बैठे हुए जज के द्वारा होनी चाहिए। आखिर पता तो चले कि एक अरसे के बाद ऐसा शासन आ गया है जहां विद्यार्थियों की बात नहीं सुनी जा रही है। और मैडम, आप जानती हैं कि जब विद्यार्थी व्याकुल हो जाते हैं, जब नौजवान व्याकुल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की जो परिस्थिति है, वह और ज्यादा खराब होने की स्थिति में पहुंच जाती है।

गन्ना किसानों का भुगतान पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है और पूरे प्रदेश में हमारे किसान इसे प्रभावित हैं। ऐसे सूरतेहाल में मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहूंगा कि इन तमाम चीजों पर तबज्जह करें। उत्तर प्रदेश में एक चुनौती हुई सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? इसकी जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चा की है। यह उत्तर प्रदेश के लिए कितना अभिमानावक अवसर है कि वहां के लोगों को वह अधिकार जो उन्होंने वोट के जरिए हासिल किया है, उनको एक लोकप्रिय सरकार नहीं दी जा रही है। किसकी जिम्मेदारी है यह? केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सब की जिम्मेदारी है और विशेष तौर पर उनकी जिम्मेदारी है जो सत्ता में बैठे हुए केन्द्र सरकार चला रहे हैं, पूरे देश के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आप अपने कंस्टीट्यूटेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते? उनको निर्देश नहीं दे सकते? उनसे कह नहीं सकते कि सिर जोड़ कर बैठिए और वहां पर एक विकल्प निकालिए? अगर आपको राज्यपाल से इतनी ही शिकायत है कि राज्यपाल इस तरह की परिस्थिति ला रहा है तो वह तो अपनी जगह पर है लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी तो इस बारे में बराबर कहती चली आ रही है कि वहां पर एक सरकार दीजिए, एक लोकप्रिय सरकार दीजिए और मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से दिलचस्पी के साथ वहां सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। कितने अफसोस की बात है कि जो मसले हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान जो हमारी राजनीतिक अट्रैक्टिविटी है, ये भवन हैं, संसद है, विधान सभाएं हैं, उनको करना चाहिए पर आज वे मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या कहता है? यह बहुत ही

گھر-ماملی سٹیویشن ہے اور اسکے ऊपर केंद्र सरकार को तज्ज्ञ करनी चाहिए, प्रधान मंत्री जी को करनी चाहिए, गृह मंत्री को भी करनी चाहिए। मिनट्री के अंदर जो जिम्मेदार विभाग है, उनके देखना चाहिए न कि अलग से जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में हमेशा अपनी राजनीति का झंडा लहराना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि वे एक्स्ट्रा-कंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं जो इस तरह से वहां पर इंटरवीन कर रही हैं। तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। इस संबंध में और चर्चा करने का मौका मिलेगा ऐसा मैं समझता हूँ लेकिन तुरंत इस सरकार को इस पर चर्चा के लिए... (व्यवधान)...

السيد سبط رضى: ابھی کچھ دیر پہلے جو نظارہ آپ نے دیکھا کہ ایک کڑ تلہ کر یا اور دوسرا کڑ تا اس پر برقی کر یا اور اس کے بعد خود خرابا ہو تلہ بالکل آٹھ نو سال سے ہمارا اثر پر دیش انہیں گتی ودھیوں کا شمار ہو رہا ہے۔ ایک طرف سام پر انگ تقو کچھ اور بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کے جواب میں کچھ سو۔ کالا سیدو ڈو سیکولر سٹ جو ہیں ان کے بڑھتے ہیں۔
...مداخلت...

شوی ترویجی ناخو چتر ویدی: ہمیں بھی کہہ دیجئے۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ "مداخلت"۔ سید سبط رضى: ہمارے دیش کی کروڑوں کروڑ جنتا آج گرسٹ ہے۔ پر جھلوت ہے ایسی چیزوں سے۔ وکاس رکاوٹ ہے۔ وکاس کی کوئی گتی ودھی نہیں ہو رہی قانونی طور سے بالکل چر مرا گئی ہے۔ پچھلے تین چار مہینے کے

انور و شیش عود سے پر شاسن نیچ پنچ ہو گیا ہے۔ ایک وسفونٹک استحقی بر پر انور و شیش عود سے اس بات سے تو دور رائے نہیں ہو سکتیں۔ جو حقیقی ہو رہی ہیں اس میں سلسلہ نا حرکت کی بات کیا کی جائے۔ کپتان مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کپتان مارے جا رہے ہیں۔ ایس ڈی ایم مارے جا رہے ہیں۔ سابق پر دھان مشری کا گھر سرکشت نہیں ہے۔ لاکھڑے کا ریکر تاسے گھر سے مارے جا رہے ہیں۔ راجنیک حقیقی ہو رہی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ برہم دت دوری کی بھی حقیقی حقیقاؤں کی ایک کڑی ہے۔ لیکن بری ہم نے امیشو کو راجنیک امیشو بنا کر حقیقاؤں کے حقت کے جی میں ان کے اوپر بات نہ کر کے اسی استحقی کے اوپر جنتا کا دھیان آکر سٹ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ سی۔ بی۔ آئی۔ انکو اٹری کی ہم نے ڈمانڈ کی ہے۔ سی بی آئی انکو اٹری کی بات مافی جا چکی ہے۔ میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی بڑی طرح سے انکو اٹری ہونی چاہئے۔ جانچ بچا ہونا چاہئے اور یہ راجنیک حقیقی جو ہیں بند ہونا چاہئیں۔ (میں ہمارے ساتھی نے یہاں پر کہا۔ میں اسپیشٹ کہتا چاہوں گا کہ یہ دیکھنا ہو گا کہ لاج اثر پر دیش میں

میں اپنا پرکاش نہیں کرتے۔ اب ذمہ داری
۴۱ قی ہے کینڈر سرکار کی۔ یا تو وہاں سے راجیہ
پال کو ختم کر دیں۔ استعانا حضرت کریں۔ یا
وہاں پر کوئی ایسی کمیٹی بنائیں جو منسود
مسودہ میں کمیٹی ہو۔ آل ہارڈ کمیٹی ہو۔
وہاں پر جانکر ایک ایک ٹکڑے کے لئے کہ
وہاں کی ہر مستحق جو ہے وہ اتنی ادھک
خواب لکھوں ہو رہی ہے۔

آج اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا
پارٹی نے جس طرح کا فیصلہ کیا ہے۔ میں
اس کے حق اور اوگن میں نہیں جانا چاہتا تھا
کہ ہمیں آپنے اس پر اس سے جس طرح قانون
لیجسلاچر میں لے لینے کا اپنے اپنے کیوں کر
آحوال لیا ہے وہاں پر مسودہ وارٹی سپریشن
نہ ہو جائے۔ ... مداخلت ... لپٹے نہ
ہے۔ یہ پال کو راجیہ جیوں سے نکلنے
نہیں دیتے اور اگر راجیہ پال راجیہ جیوں
سے نکلے کسی بیلک فنکشن میں جائے
تو ہم انکار کر دیتے۔ نشیہ روپ میں
وہاں پر ایک ٹکڑے کی ہر مستحق پیدا ہوگی۔
ایسے غریب دارانہ بیاضات سے کسی مسودہ
کا مسادہاں نہیں ہونے چاہیے۔ مگر
روپ سے ہم سبکو سر جوڑ کر بیٹھا چاہئے۔
یہی وہاں راشٹریہ درشتی کون سے کوئی
لام غلط ہو رہا ہے۔ نہت مسودہ جیوں

جو ہر مستحق ابھر کر آ رہی ہے اس کی زیادہ
ذمہ داری۔ پرتیکش روپ سے ذمہ داری
کس کی ہے۔ ٹیکس ہے ایک انسٹی ٹیوشن
کوڑے پیاں پر جو بھی کہا اس کے گن اور اوگن
میں میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن ملک روپ
سے اتر پردیش میں جو ہو رہا ہے۔ جنتا پارٹی
پریشانیوں سے گزر رہی ہے اس کی ذمہ داری
سنیکٹ مورچہ سرکاری ہے۔ اور جے کھڑے
ہے کہ سنیکٹ مورچہ کی سرکار وہاں کے ذمہ دار
منتری گن جو ہیں وہ راج جیوں کو اپنے نجی
راجنیک مسودہ جیوں کے استعمال کر رہے
ہیں۔ میں اس بات کو پوری شرمناک سمجھتا
ہوں۔ اس سے پہلے بھی اتر پردیش میں کئی
بار اس طرح سے راشٹریہ شناسن ہو چکا
ہے لیکن اس پوری گرجا کو بنائے رکھنے
کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ
راجیہ پال جی ہیں وہ پوری طرح سے ممکن
نہیں ہیں۔ جب ان پر پرتیکش روپ سے
ایسپریشن کا سٹ کے جا رہے ہیں۔ وہ
نفسندہ طور پر ایک بحث کا حقہ بنی
چکے ہیں تو اس سرکار کو دیکھنا چاہئے کہ
کس طرح سے اتر پردیش میں وہ اپنی ذمہ داری
نبھائیں۔ راجیہ پال کا شناسن اسٹ
سیلف کچھ شناسن نہیں ہوتا۔ جب تک
راشٹریہ یا کینڈر سرکار اس کے سمجھنے

کو وہاں گھومتا کیا جا رہا ہے اور نشیمن
روپ سے یہ جو اخلوہوں میں عجیب دہا
ہے۔ اس سے بہت چلتا ہے کہ وہاں پر مشا پوت
غندہ گردی ہو رہی ہے۔ اب یوری ایسی
مستابو شفت غندہ گردی ہو گی تو نشیمن
روپ سے ہم سمسہ سمسہ کی بجائے
بنتی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائی۔
ابھی ہمارے میں جیسے ہوا۔ بنارس
میں نئے و دیار تھیوں کے اوپر کھلے عام
گوئی چلائی گئی۔ یہ بہت ہی شرمناک گھٹنا
ہے۔ آج اتر پردیش کے اندر یوری کوں گروپ
کوئی سمسہ دئے۔ کوئی بھی گٹ یوری وہاں
کے شماس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے
تو اسکو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کی رہنمائی
صفتیا کرادی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی غلط
بات ہے۔ و دیار تھیوں پر گوئی چلا نا ایک
بہت ہی افسوس منہ دہ گھٹنا ہے۔ اسکی
پوری طرح سے جانچ ہونا چاہیے۔ اور میں تو
کھو نکلا کہ اسکی جانچ کسی ہائی کورٹ کے پیش
ہوئے جج کے دوا رہونا چاہیے آخر بہت تو
چلے کہ ایک عرصہ کے بعد ایسا شماسی آگیا
ہے جہاں و دیار تھیوں کی بات نہیں سنی جا
رہی ہے۔ اور میٹرم۔ آپ جانتی ہیں کہ جب
و دیار تھی ویا کل ہو جائے ہوں۔ جب تو جہاں
ویا کل ہو جاتے ہیں تو نشیمن روپ سے پڑش

کی جو بر مستحق ہے وہ اور نیک خراب ہونے
کی استحقاق میں پہنچ جاتی ہے۔
گٹا کسانوں کا جگستان پوری طرح سے
نہیں سو پار ہا ہے اور پورے پڑش میں
ہمارے کسان اس سے پر عداوت ہیں۔ اس
صورت حال میں آپ کے مادہ ہم سے سرکار
سے یہ چاہو نکلا کہ ان تمام چیزوں پر
وہ توجہ کرے۔ اتر پردیش میں ایک
جینی ہوئی سرکار کیوں نہیں بن پار رہی ہے۔
اسکی بھی ذمہ داری سنیٹک مورچہ کی
ہے۔ وں اتر پردیش کے یہ کھٹا اچھا
او مسہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو وں ادھیٹا
جو انھوں نے ووٹ کے ذریعہ حاصل کیا
ہے۔ انکو ایک نوک پر کے سرکار نہیں دی جا
رہی ہے۔ کسی کی ذمہ داری ہے۔ کیوں
ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری
ہے اور نشیمن طور پر انکی ذمہ داری ہے
جو مستابو میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سرکار
چلا رہے ہوں۔ پورے دیش کے اوپر حکومت
کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کنسٹیٹیوشن کو
نکھول نہیں کر سکتے۔ انکو پردیش نہیں دے
سکتے ان سے کہہ نہیں سکتے کہ سر جوڑ کر
میٹرم اور وہاں پر کلپ نکالنے۔ اگر آپکو
و راجیہ پال سے اتنی ہی شکایت ہے کہ راجیہ
پال اس طرح کی بر مستحق لارہے ہیں تو

وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن انہیں بھی خبر ہو چکی ہے۔
ہے۔ کانگریس پارٹی کو اس بارے میں برابر
کہتی چلی آرہی ہے کہ وہاں پر ایک سرکار
دیجئے اور ایک روپ پرے سرکار دیجئے
اور میں سمجھتا ہوں کہ بدین روپ سے پیچھے
کے ساتھ وہاں سرکار بنانے کا پرہیز نہیں
کیا گیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو
مسئلہ ہیں۔ انکا اسمادھان تو ہماری
راجنیشک اٹالیگا میں ہیں یا بھون ہیں
سنسویج۔ ورحان سمجھائیں ہیں۔ انکو
کھرنا چاہئے مگر آج وہ معاملہ کورٹ میں
پڑے ہوئے ہیں اور ہم انتظار کر رہے
ہیں کہ کورٹ کیا حکم دے گی یہ بہت ہی غریب
سبجوا ایش ہے۔ اور اس کے اوپر کئی سرکار
کو توجہ کرنی چاہئے۔ پردھان منتری جی
کو کرنی چاہئے۔ مگر منتری کو بھی کھرنا
چاہئے۔ منتری کے انور جو ذمہ دار
وہاں ہیں انکو دیکھنا چاہئے نہ کہ الگ
سے جو لوگ ہیں جو ان پر دیش میں ہمیشہ
اپنی راجنیشی کا جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سرکار مانسے ہو
اتھانے میں جو اس طرح سے وہاں پر انور
کر رہے ہیں۔ تو بہر مستحق بہت کم ہیں۔
اس سمجھوتہ میں اور چرچہ کرنے کا موقع
میں کا ایسا میں سمجھتا ہوں لیکن کورٹ

اس سرکار کو اس بار چرچہ کرنی چاہئے۔
... تھرا خالت ...

श्री अजीत जोगी: यह मौका अभी मिलना चाहिए। महोदया, यह बहुत गंभीर विषय है। इस पर गृह मंत्री को वहां कुछ कहना चाहिए। ... (व्यवधान)...

श्री एस० एस० अहलवालिया (बिहार): गृह मंत्री को बुलाया जाए। ... (व्यवधान)...

श्री अजीत जोगी: हमें हक़स नहीं चलने देना चाहिए। ... (व्यवधान)...

श्री एस० एस० अहलवालिया: मैडम, गृह मंत्री जो आएँ वहाँ पर।

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला (पंजाब): गृह मंत्री को बुलाओ। ... (व्यवधान)...

श्री एस० आर० बोम्बई: मैडम... (व्यवधान)...

श्री अजीत जोगी: मैडम, और लोगों को भी बोलने दिया जाए। ... (व्यवधान)...

उपसभापति: मिस्टर बोम्बई कुछ बोल रहे हैं। ... (व्यवधान) ... वे सरकार की तरफ से कुछ बोल रहे हैं। ... (व्यवधान) ... देखें, क्या कह रहे हैं? मालूम तो पड़े क्या कह रहे हैं? ... (व्यवधान)...

SHRI SATISH AGARWAL: The Home Minister should be asked to come before the House and make a statement.

उपसभापति: सुन लीजिए... सुन लीजिए, वे क्या कह रहे हैं? ... (व्यवधान) ...

सैयद सिद्दique रज़वी: गृह मंत्री को तुरंत आ कर वहां इतरकीन करना चाहिए। ... (व्यवधान)...

السید سید رضی: مگر منتری کو توجہ نہ کرو
یہاں انٹرو میں کرنا چاہئے۔ "مہرا خالت"۔

उपसभापति: मैं सुनू तो सही बोम्बई को क्या कह रहे हैं? ... (व्यवधान) ... आप लोग बैठें तो कुछ पूछेंगी। ... (व्यवधान)...

श्री अजीत जोगी: गोली मार रहे हैं... छात्रों को गोली मार रहे हैं। ... (व्यवधान)...

उपसभापति: जरा इनकी बात सुन लीजिए।
फिर उसके बाद जो करना है कर लीजिएगा।
...(व्यवधान)...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Let the Home Minister be called. (Interruptions)

SYED SIBTEY RAZI: Madam, I agree with my hon. colleagues. The Home Minister should be summoned. (Interruptions).

SHRI JITENDRA PRASADA (Uttar Pradesh): Madam, you direct the Government to call the Home Minister. (Interruptions)

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, call the Home Minister. We are not prepared to listen to the Human Resource Development Minister. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to me. (Interruptions)

श्री अजीत जोगी: हिन्दू यूनिवर्सिटी में छात्रों को गोली मारकर बिछा दिया गया। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: वहां कोई भी घटना घट सकती है। वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश): पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है। वहां हत्याएं हो रही हैं।
...(व्यवधान)

श्री एस०एस० अहलुवालिया: प्रधान मंत्री को बुलाया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री अजीत जोगी: मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं। बी०एच०

यू०के० के छात्रों को मारकर गटर में फेंक दिया गया, उनका पोस्ट मार्टम नहीं करवाया गया। ...(व्यवधान)

श्री सैयद सिब्ते रज़ी: उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। इसका स्पष्टीकरण देने के लिए गृह मंत्री को यहाँ तशरीफ लाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: यह बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को टाला नहीं जा सकता। ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to me. Otherwise, I will adjourn

the House. (Interruptions) The House is adjourned for lunch till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty-eight minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at six minutes past two of the clock, The Vice Chairman (Shri G. Swaminathan) in the Chair.

SYED SIBTEY RAZI: Where is the Home Minister, Sir? We have raised this issue in the morning. (Interruptions)...

SHRI SATISH AGARWAL: We have asked for Home Minister. (Interruptions)... We want the Home Minister to come and make a statement. (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Minister of State for Parliamentary Affairs is there. He wanted to say something.

SHRI SATISH AGARWAL: What does he want to say?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Sir, the hon. Home Minister is held up in the other House. In the light of the discussion of this morning, I have discussed this issue with the hon. Home Minister. Since he is held up in the other House he wanted me to make a commitment here in this House.

Sir, the Government had noted the grave concern expressed by the hon. Members during Zero Hour this morning about the law and order situation in U.P. If the hon. Members bring a motion under any regular rule and the Chairman accepts and directs the Government, the Government will not have any objection to having a discussion on this issue on any mutually acceptable time and date. The Government is ready to have a discussion, Sir, if the Chair directs.

SHRI SATISH AGARWAL: A discussion is already going on. A regular

motion under rule 168 is there. A regular motion on which a vote has to be taken has already been noticed. We have already given notice. It is already pending. (*Interruptions*)...

श्री गुफरान आजम (Madhya Pradesh): क्या होम मिनिस्टर आ रहे हैं।... (अवधान)

SHRI SATISH AGARWAL: It is already pending. A motion under rule 168 is pending. (*Interruptions*)...

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Your notice has not been accepted by the Chairman. (*Interruptions*)...

SHRI SATISH AGARWAL: A discussion is going on. (*Interruptions*)...

SHRI S.R. BOMMAI: Your notice has not been accepted by the Chairman. (*Interruptions*)...

SHRI SATISH AGARWAL: That is technical. You are too technical. A discussion is going on. Members will speak on this subject. How can you prevent Mr. Pranab Mukherjee and other Members from speaking? It is agitating the minds of the Members.

SHRI SIKANDER BAKHT: When we were talking informally I was given to understand that the Government was believed to have agreed to a discussion under rule 176. Therefore, let there be no more confusion whether we are going to have a discussion or not. Let it be understood clearly that we are going to have a discussion under rule 176, Short Duration Discussion, on the issue of prevailing condition in Uttar Pradesh. Let us have a very straight-forward commitment on that.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I had a discussion with the Minister of State for Parliamentary Affairs. The discussion could be raised in two ways. As my colleague, Mr. Satish Agarwal has pointed out, a motion has already been moved under rule 168. When we discussed it with the Minister of State for

Parliamentary Affairs we agreed that instead of having it under rule 168 we will give a motion under rule 176... (*Interruptions*)...

SHRI SIKANDER BAKHT: We will get our earlier motion converted into one under rule 176.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: ...or we can convert it into a discussion under rule 176. It is a question of technicalities because the Chairman will have to formally approve that motion. But it is agreed by all sides including the Government that a discussion on the situation in U.P. will take place under rule 176. That is the firm commitment we are having. Mr. Vice-Chairman, Sir, I think with this, the impasse can be overcome and we can start the normal business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Minister has agreed that there will be a discussion; after its acceptance by the Chairman a date and time would be fixed and at that time the Home Minister would also be present in the House and the discussion would take place. There will be no problem. It is all right.

STATEMENT REGARDING ORDINANCE

Lalit Kala Akadami (taking over of management) Ordinance, 1997

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Sir, I beg to lay on the Table a Statement (in English and Hindi) explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the Lalit Kala Akadami (Taking over of Management) Ordinance 1997. [Placed in Library. See LT 1361/97]